(d) Firm targets/allocation for electrification projects during 8th Plan period are to be fixed. However, electrification of the following routes are planned for completion during 8th Plan:—

Section	RKMs
1. Itarsi-Nagpur	298
2. Badnera-Wardha	99
3. Durg-Nagpur	265
4. Diva-Panvel	24
5. Itarsi-Bhusawal	301
6. Bina-Katni-Bilaspur (including Annuppur-Bishrampur/Chirimiri)	765
7. Jolarpettai-Bangalore	144
8. Morappur-Erode and Salem-Mettur Dam	170
9. Kazipet-Sanatnagar	167
10. Palsora Makarawan-Bhopal	216
11. Patratu-Sonenagar	291
12. Sitarampur-Mughalsarai	(Works stand forzen)
Total	2740 Kms.

Allotment for Railway electrification projects during the current year i.e. first year of the 8th Plan is Rs. 230.60 crores.

(e) Does not arise.

Benefit to Farmers on account of increased procurement price

1121. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the estimated amount likely to be given to the farmers with the recent increase in the procurement prices for 1989-90 crop season and 1990-91 Kharif crops;

(b) what is the break up of the estimated amount by which the farmers would be benefited state-wise; and

(c) what is the basis on which the estimated amount of benefits has been calculated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मनमाड-पूर्ण रेलवे लाइन के निर्माण के लिये धन का आंवटन न किया जाना

1122. **डा० बापू कालदाते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानमाड पूर्ण (दक्षिण-मध्य रेलवे) के मीटर गेज के नाम में इसलिये बड़ी रुकावट आई है क्योंकि मनमाड और अंकाई के बीच का करीब

4 किलोमीटर का क्षेत्र मध्य रेलवे के तहत पड़ता है और दूसरे वहां रेल लाइन बिछाने के लिये करीब साढे आठ करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्जफर्नांडिज) : (क) और (ख) मध्य रेलवे को मनमाड-पर्ली वैजनाथ मीटर लाइन खंड के आमान परिवर्तन के संबंध में मनमाड और अंकाई में जंक्शन प्रबंध करने हैं । मध्य रेलवे द्वारा प्रस्तुत जंक्शन प्रबंधों के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

मजदूरों के कल्याण के लिये विधान

1923. **डा० रतनाकर पाण्डेय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूरों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग ने क्या-क्या विधान बनाये हैं ;

(ख) उनके विकास के लिये क्या-क्या योजनाएं लागू की गई हैं, और

(ग) इन योजनाओं से मजदूर किस प्रकार लाभान्वित होंगे ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान : (क) से (ग) सरकार द्वाराअगस्त 1987 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के विचारार्थ विषयोंमें श्रमिकों के कल्याण, के लिए विधान बनाने की व्यवस्था नहीं है । तथापि, आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय "विद्यमान कानून और अन्य उपबन्धों का अध्ययन करना, जिनका उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है और इन उपायों तथा साथ ही उचित प्रशासनिक उपायों और डिलीवरी सिस्टम की कारगरता का मूल्यांकन करना है ।" विद्यमान कानूनों का अध्ययन करने और विद्यमान कल्याण उपायों का मूल्यांकन करने के पश्चात, आयोग से 31 मार्च, 1991 तक अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने की आशा की जाती है ।

Decrease in dependency on agriculture

1124. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to bring down the number of agro-based people to fifty percent by decreasing the dependency on agriculture, equalising the income of agriculture sector at least to the minimum level of income of organised sector and allocation of one third of the total agricultural income for the cause of women; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) No specific proposals to reduce the population dependent on agriculture to 50 per cent, allocation of a third of the agricultural income to the cause of women and equalising the income level of agricultural sector to the minimum level of the organised sector, are under consideration. These aspects are to be generally dealt with in the Agricultural Policy Resolution, under preparation.

Capital Loans to processing units

1125. SHRI A. G. KULKARNI:
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the figures of the amount disbursed either as share capital or loans to sugarcane processing units, horticulture processing units, cotton ginning and cotton spinning units in Maharashtra /Karnataka/ Haryana/ Punjab, Uttar Pradesh etc. during the last three years;